JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार का राजस्व प्रशासन (1765–1773) : एक ऐतिहासिक अध्ययन

RAVI KUMAR GIRI, RESEARCH SCHOLAR,DEPARTMENT OF HISTORY RKDF UNIVERSITY RANCHI JHARKHAND

सारांश : बिहार की विजय आसान साबित हुई। लेकिन अंग्रेजों को बिहार में बहुत कुछ नहीं मिला। प्रारम्भ में मुख्य ब्रिटिश चिंता प्रांत से राजस्व का संग्रह था, एक अधिकार जिसे उन्होंने 1765 में दीवानी प्राप्त करके हासिल किया था । एक नया राजस्व प्रशासन बनाने में असमर्थ, अंग्रेजों को मौजूदा व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ा, जो आम तौर पर नवाबों के अधीन प्रभावी ढंग से काम नहीं करती थी। अंग्रेज आसानी से सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर सकते थे, लेकिन राजस्व के उच्च स्तर को बढ़ाना उनके बस की बात नहीं थी। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन में हाथ आजमाया। उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रयोग किया 1766 और 1786 के बीच पहले राजस्व की नियंत्रण परिषद के अधीन, फिर राजस्व की प्रांतीय परिषद के तहत और अंत में राजस्व समिति के अधीन। इन प्रयोगों के परिणाम, जैसा कि हम निश्चित रूप से देखेंगे, बहुत प्रभावी साबित नहीं हुए। यह अध्ययन 1765 और 1773 के बीच राजस्व नियंत्रण परिषद के कामकाज से संबंधित हैं।

मुख्य शब्द : बिहार सरकार, राजस्व प्रशासन, राजस्व नियंत्रण परिषद, आर्थिक परिवर्तन आदि।

राजस्व प्रशासन और राजस्व नियंत्रण परिषद (1765 से 1773) : अंग्रेजों की ओर से बिहार पर अपना अधिकार स्थापित करना कोई बहुत आसान कार्य प्रतीत नहीं होता था। बक्सर की लड़ाई के अंग्रेजों को बिहार में तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें बिहार सरकार मिली, जो खराब थी । वर्तमान दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश किए बिना, उन्होंने पूरे नागरिक प्रशासन को नायब नाजिम के हाथों में छोड़ दिया। सबसे बढ़कर वे देश की आंतरिक राजनीति में शामिल हो गए। दूसरे, बिहार अपेक्षाकृत गरीबी से ग्रस्त होने के कारण, दीवानी के अधिग्रहण के बाद अंग्रेज अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बिहार से राजस्व वसूल करने में सक्षम नहीं थे (जो उनकी प्राथमिक चिंता थी)। इसके अलावा उन्हें राजस्व वसूली में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तीसरे उन्हें प्रांत में शत्रुतापूर्ण तत्वों से निपटना पड़ा। जमींदार द्य बिहारी जमींदार बंगाल के जमींदारों जितने शक्तिशाली नहीं थे। हालाँकि, अधिकांश समय उन्होंने राजस्व का भुगतान रोक दियाय और उन्होंने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया । इसलिए बिहार की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण अंग्रेज बंगाल की तरह बिहार से लाभ नहीं उठा पाए । यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन समस्याओं से कैसे निपटा और वे बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कहाँ तक सफल रहीं और अधिक विशिष्ट होने के लिए, वे राजस्व के संग्रह में कहाँ तक सफल रहीं जो उनके लिए प्राथमिक महत्व का था । सन् 1757 में बंगाल में जो मोड़ आया वह बेशक रक्तहीन नहीं था। प्लासी के युद्ध में सिराज की हार ने अंग्रेजों को बंगाल का निर्विवाद स्वामी बना दिया। प्लासी के युद्ध की गूंज बिहार में भी बक्सर की लड़ाई के रूप में सुनाई दी, जो 1764 में बहुत बाद में लड़ी गई थी । प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल के निर्विवाद स्वामी के रूप में स्थापित किया और बक्सर ने उन्हें निर्विवाद रूप से स्थापित किया। बिहार के स्वामी । लेकिन बंगाल के विपरीत, बिहार में, बक्सर की लड़ाई से बहुत पहले, अंग्रेजों ने अपने नायब नाजिम राजा रामनारायण को अपना नायक बनाकर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी। बिहार में पहले से ही ब्रिटिश सेना तैनात थी। हालाँकि मीर

जाफर इस व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी मीर कासिम अलग साबित हुए। बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गया था, वह बिहार को अपना गढ़ बनाना चाहता था, जिसके उद्देश्य से उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का कष्ट उठाया। रामनारायण को लेकर मीर कासिम और पटना कारखाने के प्रमुख एलिस के बीच अनबन शुरू हो गई और अंततः मीर कासिम ने उन्हें मरवा दिया। प्लासी ने एक असहाय नवाब की हार देखी, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन बक्सर में अंग्रेजों को मीर कासिम, अवध के शुजा–उद–दौला और तत्कालीन सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। दिल्ली का । इसलिए उनके बहुत प्रयास से कंपनी बिहार पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही । तब अंग्रेजों के सामने सूबे पर अपने प्रशासन को मजबूत करने की समस्या थी । अगस्त 1765 में दीवानी के अधिग्रहण के बाद ब्रिटिश हित मुख्य रूप से प्रांत के राजस्व प्रशासन पर केंद्रित थे, नागरिक प्रशासन को नायब नाजिम के हाथों में छोड़ दिया गया था। अंग्रेजों ने रामनारायण के भाई धीरज नारायण को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो उनके बाद बिहार के नायब नाजिम के रूप में सफल हुए। लेकिन बाद में धीरजनारायण को गबन के आरोप में हटा दिया गया । अंग्रेजों ने रेजा खान और शिताब राय को भी नियंत्रित किया, बाद में धीरज नारायण के उत्तराधिकारी बने। बाद में जब हेस्टिंग्स को लगा कि कंपनी ही नागरिक प्रशासन चलायेगी, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हटा दिया गया । 1765 और 1769 के वर्षों के बीच अंग्रेजों की दिलचस्पी मौजूदा दोषपूर्ण राजस्व प्रशासन में सुधार की कोशिश किए बिना बिहार से जितना राजस्व प्राप्त किया जा सकता था, वसूलने में थी। जून 1770 में ही उन्होंने राजस्व प्रशासन में गहरी दिलचस्पी ली। बिहार के विभिन्न परगना में अंग्रेजी पर्यवेक्षकों को भेजने की योजना । कुछ समय बाद सितंबर 1770 में बिहार प्रांत के राजस्व को प्रशासित करने के लिए राजस्व नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। राजस्व की नियंत्रण परिषद बहुत सफलतापूर्वक कार्य नहीं करती थी । पर्यवेक्षक भ्रष्ट हो गए। उन्होंने अपने बनियों को परगना पट्टे पर दे दिए और अधिकांश धन हड़प लिया । इस संबंध में हम मुंगेर के पर्यवेक्षक नथानिएल बेटमैन के मामले का हवाला दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्व प्रशासन में अन्य कठिनाइयाँ थीं। इसलिए इसे दिसंबर 1773 में राजस्व की प्रांतीय परिषद की स्थापना के साथ समाप्त कर दिया गया, जो 1781 तक कार्य करती रही । सितंबर 1781 में, बनारस के राजा चौत सिंह और बिहार के कुछ जमींदारों के विद्रोह के साथ इसे समाप्त कर दिया गया। बिहार की राजस्व स्थिति बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है । जहाँगीर के शासनकाल की शुरुआत से मुहम्मद शाह के समय तक बिहार का राजस्व पूरी तरह से वसूल किया गया था । मुजफ्फर आलम फारसी अभिलेखों का हवाला देते हुए सुझाव देते हैं कि प्राचीन मानक एक करोड़ रुपये था। 5 जागीरों और निजामत के शुल्कों के रूप में एक निश्चित राशि काटने के बाद, लगभग अस्सी – एक लाख का एक स्पष्ट शेष बना रहा, जो मुहम्मद शाह के शासनकाल के अंत तक वार्षिक रूप से वसूल किया जाता रहा । लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या यह सच है, क्या वास्तव में इतनी बड़ी राशि बिहार से दिल्ली को राजस्व के रूप में प्रेषित की गई थी और क्या बिहार वास्तव में इतना बड़ा राजस्व प्राप्त कर सकता था, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेज अधिक एकत्र नहीं कर सके । लेकिन 1733 में शुजा खान की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के साथ चीजें बदलने लगीं। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने मीर कासिम के समय तक बिहार से दिल्ली को जितना राजस्व नहीं भेजा था । यह संदिग्ध है कि क्या उन्हें बिहार से राजस्व के रूप में अच्छी रकम मिली थी। जब अंग्रेजों ने दीवानी का अधिग्रहण किया, तो देश उथल–पुथल के बीच था। कई जमींदार शत्रुतापूर्ण थे और भुगतान से बच रहे थे। इसके अलावा भूमि का एक बड़ा हिस्सा जागीर, अल्तुमगाह, मदद माश और पेबकी खालसा शेरेसा के रूप में अलग कर दिया गया था। हालांकि ये जमीनें अच्छा राजस्व दे सकती थीं लेकिन राजस्व मुक्त स्थिति का आनंद ले रही थीं। हालांकि जागीर के मूल धारकों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनके परिवारों द्वारा उनके नाम पर दावा किया जाता था। इसने बहुत भ्रम पैदा किया । ऐसे कई गाँव और तालुक भी थे जो नाजियों के सनदों द्वारा उनके मूल्य से बहुत कम एक निश्चित किराए पर रखे गए थे और कई ऐसे थे जो एक लंबे कब्जे के दावे के साथ आयोजित किए गए थे। अंग्रेज इन जागीर भूमि को वापस लेना चाहते थे लेकिन किसी न किसी कारण से इस प्रक्रिया में देरी हो रही थी । यह बहुत स्पष्ट था कि अगर इन जागीरों को फिर से शुरू किया गया तो प्रांत के राजस्व में कुछ हद तक वृद्धि होगी। लेकिन जेम्स ग्रांट का अनुमान था कि 9,26,643 रुपये 1765 और 1767

के बीच जागीर के रूप में अलग कर दिए गए थे। यह मुजफ्फर आलम के लिखे के विपरीत है। उनका विचार था कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जागीर के रूप में अलग कर दिया जाता था । यह सत्रहवीं सदी का सच हो सकता है लेकिन अठारहवीं सदी का नहीं । तो ऐसा लगता है कि बिहार जागीरों में अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खो नहीं रहा था । बंगाल में जागीर भूमि को वापस लेने का यह प्रयास सफल रहा और इसमें कम समय लगा लेकिन बिहार के मामले में ऐसा नहीं हुआ । बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की अधिकांश जागीर भूमि को उड़ीसा में स्थानांतरित करके पूरे प्रांत को खालसा में परिवर्तित करने का प्रयास किया। बिहार में इसी तरह की व्यवस्था फखर–उद–दौला ने 1731–32 में सोची थी । लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, उन्होंने अपनी सूबेदारी खो दी। बिहार के नायब नाजिम शिताब राय, पटना कारखाने के प्रमुखों के साथ मिलकर, पहले थॉमस रूंबोल्ड और फिर जेम्स अलेक्जेंडर राजस्व संग्रह में बहुत मेहनती साबित हुए। वे बाधाओं से मिले और बिहार में राजस्व संग्रह में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ सामने आए लेकिन बोर्ड द्वारा उनकी योजनाओं पर शायद ही कभी ध्यान दिया गया ।

बिहार की राजस्व संरचना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। इस संरचना में विभिन्न एजेंट शामिल थे जो विभिन्न स्तरों पर कार्य करते थे। सबसे निचले स्तर पर रैयत थे, जो मिट्टी को जोतते थे, जो राजस्व देते थे । राजस्व वसूल करने वाले आमिल थे। इसके बाद जमींदार थे, जिनकी जमीन पर रैयत खेती करते थे। जमींदारों को सरकार को राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। जमींदार बदले में रैयतों से राजस्व वसूल करते थे। जहां जमींदार नहीं थे, वहां बड़े किसान थे, जो जमींदारों की तरह ही काम करते थे। बाद में नियंत्रक परिषद और राजस्व की प्रांतीय परिषद के तहत इन किसानों को किराएदार कहा गया। इन तत्वों के अलावा, अनगिनत छोटे जमींदार या मलिक थे, जो खुद अपने नियंत्रण वाली थोड़ी सी जमीन को जोतते थे। केवल जागीरदारों को किसी भी राजस्व का भुगतान करने से छूट दी गई थी, इसके बजाय, उन्हें अपने रखरखाव के लिए राज्य से भत्ते मिलते थे। प्रत्येक जिले का अपना कलेक्टर होता था, जो लगान वसूल करता था । इन्हीं कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को भुगतान किया जाता था । उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में बुकानन हैमिल्टन के सर्वेक्षणों के आधार पर ब्रिटिश पर्यवेक्षकों के अध्ययन ने अपेक्षाकृत धनी किसानों से लेकर किसानों और मजदूरों को साझा करने तक के जटिल पैटर्न का खुलासा किया। राजस्व निर्धारण और भुगतान के तरीके के रूप में सामाजिक पदानुक्रम जिले से जिले में भिन्न होता है। निस्संदेह अधिकांश जटिलता अठारहवीं शताब्दी के बिहार में मौजूद थी, लेकिन यह शुरुआती ब्रिटिश प्रशासकों के लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। जमींदारों और किराएदारों से परे उनका ग्रामीण इलाकों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था। समकालीन ब्रिटिश रिकॉर्ड 'दंगों' (रैयतों) के बारे में सामान्यीकरण से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, जिन्हें वे समान रूप से गरीबी से पीड़ित और उत्पीड़ित मानते हैं। दीवानी के अधिग्रहण के पहले कुछ वर्षों में मुहम्मद रजा खान ने लार्ड क्लाइव के निर्देशानुसार बिहार प्रांत का बंदोबस्त तय कर दिया था। हालांकि संग्रह कभी भी बैंडबस्ट पर तय की गई राशि तक नहीं पहुंचा, लेकिन जेम्स ग्रांट की राय थी कि बैंडबस्ट को बहुत अधिक मूल्य पर तय किया जाना चाहिए था । शायद उनके दिमाग में मुगल काल की बैंड बस्ट थी। अब सवाल यह है कि मुगल काल से स्थिति में भारी बदलाव क्यों आया? शुजा खान के शासनकाल से राजस्व संग्रह में गिरावट की प्रक्रिया शुरू हो गई थी । गिरावट हो या न हो, लेकिन तथ्य यह था कि वह दिल्ली भेजने के लिए पूरी तरह से इच्छुक नहीं था। उनके उत्तराधिकारी सरफराज खान के मामले में भी यही लागू हुआ। लेकिन अलीवर्दी से लेकर मीर कासिम के काल तक, बिहार अफगान और मराठा आक्रमणों और बाद में अंग्रेजों के आगमन से बिखर गया था। इस सब के कारण राजस्व संग्रह काफी हद तक बाधित हुआ । उथल–पुथल का फायदा उठाते हुए जमींदारों ने सरकार को भुगतान से परहेज किया और विद्रोह कर दिया। मीर कासिम केवल एक बार जमींदारों और जागीरदारों के गुप्त संग्रह को जब्त करके बिहार से राजस्व के रूप में लगभग 65 लाख रुपये एकत्र करने में सफल रहा। यदि हम 1765 और 1773 के बीच एकत्र किए गए राजस्व की राशि का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि यह उस बंदोबस्त से बहुत कम नहीं था जो बिहार में प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में आयोजित होने वाले पुण्य में बसा था । जागीरदारों और विद्रोही जमींदारों के अलावा, जिन्होंने राजस्व संग्रह में उतार–चढ़ाव का कारण बना, राजस्व संग्रह में उतार–चढ़ाव का कारण बना, राजस्व संग्रह भी 1769–70 में अकाल के बाद सूखे से प्रभावित हुआ । रंबोल्ड के पर्यवेक्षक जहाज की अवधि के दौरान चांदी की कमी ने भी राजस्व संग्रह में उतार–चढ़ाव का कारण बना।

सन्दर्भ :

1. बर्नियर, फ्रेंकोइस। मुगल साम्राज्य में यात्रा, खंड 1 और 2, आर. सी. लेपेज एंड कंपनी, लंदन, 1826
2. बौरे, थॉमस ए ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ कंट्रीज राउंड द बे ऑफ बंगाल, 1669द्1679, हकलुइट सोसाइटी प्रकाशन, कैम्ब्रिज, 1905
3. ग्रियर्सन, जॉर्ज ए. बिहार किसान जीवन, बंगाल सचिवालय प्रेस, कलकत्ता, 1885
4. हैंड, जे. आर. अर्ली इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, 1781–85, बंगाल सेक्रेटेरिएट प्रेस, कलकत्ता, 1894
5. हेस्टिंग्स, वॉरेन, बनारस में विद्रोह की एक कथा, सी. विल्किस, कलकत्ता, 1781।
6. जेम्स, जे.एफ.डब्ल्यू. बिहार के राजस्व प्रमुख के पत्राचार से चयन, 1781 – 1786, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अधीक्षक, पटना, 1919
7. किंडरस्ले, जेमिमा , ईस्ट इंडीज के पत्र, जे. नोर्स, लंदन, 1777
8. रेनेल, जेम्स, ए बंगाल एटलस, 1781
9. टैवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट द्य ट्रैवेल्स इन इंडिया, खंड 1 और 2, मैकमिलन एंड कंपनी, लंदन, 1889
10. विल्सन, मिंडेन, बिहार इंडिगो फैक्ट्रीज एंड अदर ट्रैक्ट्स का इतिहास, कलकत्ता जनरल प्रिंटिंग कंपनी, कलकत्ता, 1908।
11. ब्रिज, टी.डब्ल्यू. पलामू जिले में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट, 1913द्1920, अधीक्षक सरकारी मुद्रण, पटना, 1921
12. बुकानन हैमिल्टन, फ्रांसिस, 1809 – 10, बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, 1934 में शाहाबाद जिले का लेखा ।
13. बुकानन हैमिल्टन, फ्रांसिस , 1811–12 में बिहार और पटना के जिलों का लेखा, खंड 1 और 2, बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, 1925
14. बुकानन हैमिल्टन, फ्रांसिस, 1812 – 1813, बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, 1926 में शाहाबाद जिले के सर्वेक्षण के दौरान रखा गया फ्रांसिस बुकानन का जर्नल।
15. हंटर, बंगाल का एक सांख्यिकीय खाता, खंड द्य 11, ट्रूबनर एंड कंपनी, लंदन, 1877
16. हंटर, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, 1996
17. हंटर,बंगाल एमएस रिकॉर्ड्स, 4 खंड, एलन एंड कंपनी, लंदन, 1894
18. जेम्स, जे.एफ.डब्ल्यू. पटना जिले (1907–1912), बिहार और उड़ीसा सरकारी प्रेस, पटना, 1914 में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट।
19. जेम्स, जे.एफ.डब्ल्यू. बिहार और उड़ीसा जिला गजेटियर – मुंगेर, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पटना, 1924।
20. केर जे.एच. सारण जिले में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट, 1893–1901, बंगाल सचिवालय प्रेस, कलकत्ता, 1903
21. मैकफर्सन एच. सोंथल परगना जिले में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट, 1898द्1907, बंगाल सचिवालय बुक डिपो, कलकत्ता, 1909
22. ओ'मैले, एल.एस.एस. बिहार और उड़ीसा जिला गजेटियर– पटना, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पटना, 1924
23. ओ'मैले, एल.एस.एस. बिहार और उड़ीसा जिला गजेटियर – शाहाबाद, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पटना, 1924
24. ओ मैले, एल.एस. एस., बंगाल जिला गजेटियर – शाहाबाद, बंगाल सचिवालय बुक डिपो, कलकत्ता, 1906
25. ओ'मैले, एल.एस.एस. बंगाल जिला गजेटियर – चंपारण, बंगाल सचिवालय बुक डिपो, कलकत्ता, 1907
26. ओ'मैले, एल.एस.एस. बंगाल जिला गजेटियर – मुजफ्फरपुर, बंगाल सचिवालय बुक डिपो, कलकत्ता, 1907

27. ओ'मैले, एल.एस.एस. बंगाल जिला गजेटियर – सारण, द बंगाल सेक्रेटेरिएट बुक डिपो, कलकत्ता, 1907
28. फिलिमोर, आर.एच. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम । 1 सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, 1945
29. स्टीवेंसन मूर, मुजफ्फरपुर जिले में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट, 1892दृ1899, अधीक्षक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता, 1901
30. स्टीवेन्सन मूर, सी. जे. चंपारण जिले में सर्वेक्षण और निपटान संचालन पर अंतिम रिपोर्ट, 1892–1899, अधीक्षक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता, 1900
31. सिफटन, जे.डी. फाइनल रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, 1908दृ1915, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, पटना, 1917
32. स्लैक, एफ.ए. छोटानागपुर के महाराजा की संपत्ति के बंदोबस्त पर रिपोर्ट, अधीक्षक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता, 1888।
33. बंद्योपाध्याय, कुमकुम ''स्वदेशी व्यापार, वित्त और राजनीति, पटना और उसके भीतरी प्रदेश का एक अध्ययन, 1757–1813, पी0एच0डी0 थीसिस, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1987
34. दत्ता, रजत,''ग्रामीण बंगालः अठारहवीं शताब्दी के अंत में सामाजिक संरचना और कृषि अर्थव्यवस्था", पीएच.डी. थीसिस, लंदन विश्वविद्यालय, 1990